मार्च 2023
खंड - XXXIX | अंक - I

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- वित्त अंतर को कम करने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना: एक जी 20 परिप्रेक्ष्य
- लोहा और इस्पात उद्योग : बदलते ट्रेंड
- भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध
- भारतीय रसायन उद्योग: विकास क्षमता की संभावनाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक
की तिमाही प्रकाशन

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

वित्त अंतर को कम करने के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना: एक जी 20 परिप्रेक्ष्य

– **जाह्नवी सिंह,** *मुख्य प्रबंधक,*
नेहा रमन, *उप–प्रबंधक*

व्यापार वित्त से तात्पर्य किसी भी प्रकार के वित्तपोषण से है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाता है। इसमें निर्यातक और आयातक दोनों के अनुकूल शर्तों पर माल या सेवा के लिए भुगतान को सुगम बनाने के लिए आवश्यक ऋण, गारंटी और बीमा शामिल हैं। व्यापार वित्त संरचना में वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, बीमा कंपनियां, निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए), बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी), वेंचर कैपिटलिस्ट, बिज़नेस एंजेल्स, फिन-टेक आदि सहित वित्तपोषण के कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोत शामिल हैं।

व्यापार वित्त में रुझान

वर्तमान समय में अधिकांश व्यापार वित्त उत्पादों में मंदी देखी गई है। साख पत्र (एल/सी) के समग्र उपयोग के अच्छे संकेतक, स्विफ्ट ट्रेड फायनेंस ट्रैफिक में 2010 के बाद से गिरावट आई है। यह 2019 में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, तथा 2020 में और गिर गया। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से कॉरेस्पॉन्टेंड बैंकिंग गतिविधियों में भी कमी आई है। इससे विकासशील देशों में व्यापार वित्त की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसके विपरीत, कुछ व्यापार वित्त उत्पादों में हाल के वर्षों में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग व्यवसाय में 2015-2021 की अवधि के दौरान लगभग लगातार वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान 2.0% की सीएजीआर दर्ज की गई। वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बहाली के साथ, अंतरराष्ट्रीय फैक्टरिंग वॉल्यूम में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2021 में 706 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। इसी तरह, वैश्विक निर्यात ऋण और बीमा भी 2017-2021 के दौरान बढ़कर 2021 में 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचे।

व्यापार वित्त के लिए चुनौतियां

अनिश्चित वैश्विक डायनैमिक्स: वैश्विक व्यापार वित्त उद्योग को भू-राजनीतिक समस्याओं, व्यापार युद्धों, संरक्षणवाद और कोविड-19 महामारी जैसे बहु-संकट के कारण उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी से व्यापार वित्त प्रदाताओं की भावनाएं और आहत हुई हैं। एक्सेंचर के अक्टूबर 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले 12 महीनों में बढ़ती ब्याज दरों से लगभग दो-तिहाई ऋणदाता फर्में प्रभावित हुई हैं। थाईलैंड, भारत, मलेशिया और सिंगापुर जैसी अर्थव्यवस्थाओं में इसका प्रभाव विशेष रूप से अधिक रहा है। इसके अलावा, व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद भी व्यापार वित्तपोषकों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। एफसीआई के एक हालिया सर्वेक्षण में, आधे से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि संरक्षणवाद व्यापार वित्त अंतर को और बढ़ा सकता है। जाहिर है, अनिश्चित वैश्विक डायनैमिक्स व्यापार वित्त के लिए एक प्रतिकूल स्थिति है।

धन शोधन निवारण (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकता: व्यापार वित्त अंतर, विकास और रोजगार पर आधारित 2021 एडीबी सर्वेक्षण के अनुसार, एएमएल/केवाईसी आवश्यकताएं व्यापार वित्त के लिए सबसे बड़ी बाधा रहीं। ये आवश्यकताएं ऋण प्रदान करने की लागत को बढ़ाती हैं क्योंकि इनके

अनुपालन में समय लगता, यह जटिल है और कभी-कभी नेविगेट करना भी मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के आधार पर आवेदन अधिक अस्वीकृत किए जाते हैं और कॉरेस्पॉन्टेंड बैंकिंग संबंधों की समाप्ति होती है। इससे बैंक ऋण छोटी फर्मों और विकासशील देशों को सीमित हो जाता है।

फिर व्यापार वित्त पर एएमएल और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के घटना-आधारित वैश्विक मानक भी लागू होते हैं। ये ऋणदाताओं में अत्यधिक व्यक्तिपरकता और अस्पष्टता के कारण बनते हैं और यदि कोई घटना होती है तो बैंकों को बड़े जुर्माने भरने पड़ते हैं। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए सीमा पार जोखिम की लागत बढ़ जाती है। फेनेर्गो की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन विनियमों के गैर-अनुपालन के कारण वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामकीय शुल्क 2007 के बाद से लगातार बढ़े हैं, जो एएमएल, डेटा गोपनीयता और ईएसजी अनुपालन उल्लंघनों से संबंधित विफलताओं के कारण 2022 तक बढ़कर 56.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए हैं। केवाईसी मानदंडों और ग्राहक सम्यक जांच (ड्यू डिलिजेंस) प्रक्रियाओं से वित्तीय संस्थाओं के लिए भी लागत में वृद्धि हुई है। केवाईसी प्रक्रियाओं ने नए ग्राहकों को जोड़ना महंगा बना दिया है। "डी-रिस्किंग" कही जाने वाली प्रक्रिया में बैंक बढ़ती अनुपालन लागत के चलते कई भौगोलिक क्षेत्रों और ग्राहक खंडों से हटने को मजबूर हुए हैं, जिससे व्यवसायों और बाजारों का वित्तीय परिसीमन हुआ है।

बेसल मानदंडों का प्रभाव: बेसल आवश्यकता का प्रभाव व्यापार वित्त के लिए एक और उल्लेखनीय चुनौती है। बेसल III में 2017 के संशोधनों के परिणामस्वरूप बैंकों को अपने कई उत्पादों के लिए अधिक जोखिम और पूंजी आवंटित करने की जरूरत है, जिससे पूंजी की कमी हो सकती है। यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण की एक हालिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बेसल III सुधार के पूर्ण कार्यान्वयन से इस क्षेत्र के 160 बैंकों के नमूने के लिए टियर 1 जोखिम-आधारित पूंजी आवश्यकताओं के लिए लगभग 0.8 बिलियन यूरो की पूंजी की कमी हो सकती है। यूरोपीय बैंकों में पूंजी की कमी का प्रभाव यूरोपीय संघ सहित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सीमा पार बैंकिंग के उच्च संकेंद्रण के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के ऋण पर भी पड़ने की संभावना है। इससे व्यापार वित्त अंतर और बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा, बेसल मानदंडों के तहत, एल/सी के लिए लीवरेज अनुपात की आवश्यकता इन व्यापार वित्त इंस्ट्रूमेंटों के कम जोखिम को प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए आस्तियों की अन्य श्रेणियों के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम मार्जिन वाले व्यापार वित्त को हतोत्साहित करता है।

एमएसएमई की व्यापार वित्त तक सीमित पहुंच: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए व्यापार वित्त की आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि उन्हें उच्च अस्वीकृति दर का सामना करना पड़ रहा है। नतीजतन, एडीबी के अनुसार, एमएसएमई के लिए वैश्विक व्यापार वित्त अंतर 2018 में 0.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 में 0.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो गया। एमएसएमई के मामले में उच्च अस्वीकृति दर के कुछ प्रमुख कारणों में ऋण आवेदनों का ऋण सहायता के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त होना, अतिरिक्त कोलैटरल की कमी और कोविड-19 से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा, एमएसएमई के बीच जागरूकता की कमी भी एक कारण है। उन्हें बैंकों में केवाईसी प्रक्रियाओं के महत्त्व और व्यापार वित्त आवेदनों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए बैंकों की आवश्यकता की भी पूरी तरह से समझ नहीं होना एक अन्य कारण हो सकता है। एडीबी सर्वेक्षण के अनुसार, 1% से कम उत्तरदाता फर्मों ने केवाईसी को अपने व्यापार वित्त प्रस्तावों की अस्वीकृति के लिए एक संभावित कारक माना, जबकि बैंकों ने केवाईसी चिंताओं को व्यापार वित्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का 5वां सबसे महत्त्वपूर्ण कारण माना।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों को असमान रूप से अपनाना: हालांकि महामारी ने डिजिटलीकरण को तेज कर दिया है, लेकिन व्यापार और व्यापार वित्त में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को असमान रूप से अपनाया जा रहा है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ बड़े निगमों और एमएसएमई के बीच डिजिटलीकरण तक पहुंच में अंतर है। व्यापार दस्तावेजीकरण में डिजिटलीकरण को अपनाने के अलग-अलग स्तरों के कारणों में से एक कानूनी ढांचे की कमी है। इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणीय रिकॉर्ड के लिए कानूनी मान्यता स्थापित कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति (यूएनसीआईटीआरएएल) ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणीय रिकॉर्ड पर मॉडल कानून (एमएलईटीआर) बनाया था। हालांकि, अब तक केवल सात देशों ने एमएलईटीआर अपनाया है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बैंकों के सामने एक और बड़ी चुनौती प्रौद्योगिकी की उच्च लागत भी है।

आगे की राह

हार्मोनाइज्ड केवाईसी मानकों की स्थापना: महामारी के बाद ई-केवाईसी को अपनाने में विश्व स्तर पर तेजी आई है। तथापि, सम्यक जांच प्रक्रिया में एकरूपता की कमी है, जिसमें विभिन्न देशों ने अलग-अलग ई-केवाईसी मॉडल को अपनाया है। जैसे भारत और जर्मनी द्वारा उपयोग की जाने वाली "वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया", और हांगकांग, मलेशिया और यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले "पहचान प्रमाणीकरण और मिलान मॉडल"। विभिन्न ई-केवाईसी मानकों से प्राप्त जानकारी की गुणवत्ता में विसंगतियां व्यापार वित्त और व्यापार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। जी20 देश सुसंगत केवाईसी मानकों को स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, जिससे स्क्रीनिंग और जोखिम मूल्यांकन आवश्यकताओं को आसान बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा लागत को कम करने में मदद मिलेगी। ई-केवाईसी मानकों को सुसंगत बनाने के अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अनुपालन जांच में सुधार और धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शनों के जोखिम को कम करने के लिए अपने पुराने प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को अपग्रेड करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

डिजिटलीकरण का लाभ उठाना: सहयोग के चार संभावित क्षेत्र हैं जिन पर जी20 व्यापार वित्त अंतर को कम करने के लिए डिजिटलीकरण का लाभ उठाने हेतु काम किया जा सकता है:

i) *कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) को अपनाना:* एलईआई एक विश्वव्यापी यूनीक पहचानकर्ता (आइडेंटिफायर) है, जो कानूनी संगठनों को वैश्विक, डिजिटल पहचान प्रदान कर डिजिटल वित्त अनुप्रयोगों और भुगतानों में अंतःक्रियाशीलता में सुधार करने में मदद करता है। वर्तमान में, एलईआई को अपनाने के मामले में दुनिया भर में और यहां तक कि जी20 देशों में भी काफी असमानता है। कुछ जी20 देशों में अन्य की तुलना में सक्रिय एलईआई की संख्या काफी कम है। एलईआई को व्यापक रूप से अपनाने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ट्रांज़ैक्शनों की दक्षता और पारदर्शिता में काफी सुधार हो सकता है। जी20 देश वित्तीय ट्रांज़ैक्शनों के लिए वैश्विक पहचान मानक के रूप में एलईआई को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जी20 देश व्यवसायों के लिए एलईआई प्राप्त करने से जुड़ी लागतों को कम करने या समाप्त करने में भी मददगार हो सकते हैं।

ii) *रिपोर्टिंग मानकों को सुसंगत बनाना:* वित्तीय स्थिरता बोर्ड की "रिपोर्ट ऑन मार्केट फ्रेगमेंटेशन" (जून 2019) में कहा गया है कि हालांकि एलईआई जैसे मानक-निर्धारकों द्वारा डेटा क्षेत्रों के लिए मानकों को सुसंगत बनाने में प्रगति हुई है, लेकिन डेटा एकत्रीकरण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जानकारी की तुलनात्मकता प्राप्त करने हेतु मानकों को लागू करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यापार वित्त ट्रांज़ैक्शनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा के उपयोग के लिए सामंजस्यपूर्ण रिपोर्टिंग मानक अहम होंगे।

iii) *एमएलईटीआर को अपनाना:* सामंजस्यपूर्ण विधायी सुधार और सामान्य मानक, जिसमें इनवॉइसिंग से लेकर वित्तपोषण उत्पादों तक, पहचान से सुरक्षा तक, व्यापार और व्यापार वित्त के डिजिटलीकरण के आवश्यक कारक हैं। एमएलईटीआर या इसके समकक्ष कानून को अपनाने से एक ऐसा परिवेश बन सकता है जो दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के लिए आसान हो और विदेशी बाजारों तक पहुंच में आसानी के लिए दस्तावेजीकरण से संबंधित गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने वाला हो। हालांकि यूके और यूएसए ने एमएलईटीआर के समान कानून बनाए हैं, तथापि, अन्य जी20 देशों ने अभी तक डिजिटल दस्तावेजीकरण को सुसंगत बनाने के लिए इस तरह के उपायों को नहीं अपनाया है। जी20 देश अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, एमएलईटीआर के लिए राष्ट्रीय कानूनों और कानूनी ढांचे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस तरह के अनुकूलन से परिवहन के दस्तावेज, लदान बिल, विनिमय बिल, वचन पत्र और गोदाम रसीदें आदि जैसे दस्तावेजीकरण की समस्याएं हल होंगी।

iv) *डिजिटल विभाजन को कम करना:* ब्रॉडबैंड पहुंच की बाधाओं को कम करने वाली नीतियां आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, और संचार ऑपरेटरों को अधिक आसानी से तथा सस्ते निवेश में मदद करती हैं। ऐसी नीतियां विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए आवश्यक होंगी। जी20 के साथ-साथ बहुपक्षीय संस्थाओं को डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश करना चाहिए। जी20 देशों को वित्तीय सेवा क्षेत्र सहित डिजिटल कौशल अंतर को कम करने के लिए मौजूदा व्यापार से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के समन्वय को बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी।

विकास वित्त संस्थाओं के बीच सहयोग: सह-वित्तपोषण / समानांतर वित्तपोषण के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी), निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) और राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) के बीच सहयोग मित्र देशों में विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और कंपनियों के लिए परियोजना निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। जी20 निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए) अलग-अलग निधीयन व्यवस्थाओं में एकरूपता लाने और अपनी विकास वित्त संस्थाओं में निधीयन लागत को कम करने के लिए अपनी सरकारों के सहयोग से आपस में सह-वित्तपोषण व्यवस्थाएं लागू कर सकती हैं। ये संस्थाएं कठिन वित्तीय परिस्थितियों के दौरान छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में एसएमई, नए निर्यातकों और फर्मों के लिए पर्याप्त फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए परियोजना तैयार करने संबंधी सुविधाओं और लिक्विडिटी पूल के निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से सूचना साझा करने और बैंक योग्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी सहयोग कर सकती हैं। इसके अलावा, जी20 देश विदेशी मुद्रा लिक्विडिटी के व्यवस्थित प्रावधान में अंतर को भरने के लिए एक नए वैश्विक लिक्विडिटी बीमा तंत्र के निर्माण पर भी विचार कर सकते हैं, ताकि अधिक मजबूत और लचीली वैश्विक वित्तीय प्रणाली तैयार की जा सके।

वैकल्पिक व्यापार वित्तपोषण: आने वाले समय में, व्यापार वित्त अंतराल को कम करने में फिन-टेक और वैकल्पिक वित्त प्रदाताओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण (एससीएफ) एक ऐसा क्षेत्र है, जहां इस तरह के सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिनटेक द्वारा प्रदान किए गए एससीएफ समाधान बैंक-मध्यवर्ती वित्तपोषण का विकल्प हो सकते हैं। फिनटेक एसएमई के लिए वित्तपोषण अंतर को कम करने के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी व्यापार प्राप्य राशियों को बेचने के लिए फिनटेक के प्रौद्योगिकी प्लैटफॉर्मों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय बुनियादी ढांचे, तकनीकी क्षमता, संसाधनों और जागरूकता की कमी के कारण एससीएफ उत्पादों की पेशकश करना मुश्किल लगता है। इसके लिए, बहुपक्षीय संस्थाएं और विकास वित्त संस्थाएं ऐसे ऋणदाताओं के एससीएफ में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी-फंडर, मिश्रित वित्त प्लैटफॉर्मों को विकसित और संचालित कर सकती हैं जो अन्यथा अपने स्वयं के एससीएफ कार्यक्रम को विकसित करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों। इसके अलावा, ये संस्थाएं एससीएफ के लिए एक सक्षम ढांचा विकसित करने के लिए विनियामकों और नीति निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू कर सकती हैं और नए उत्पादों को विकसित करने में वाणिज्यिक बैंकों को सहयोग दे सकती हैं। मेक्सिको और अर्जेंटीना जैसे कई जी20 देशों की विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआई) पहले से निजी क्षेत्र के सहयोग से एससीएफ से संबंधित उपाय कर रही हैं।

व्यापार वित्त सुविधा: विकासशील देशों की राष्ट्रीय विकास वित्त संस्थाएं (डीएफआई) और निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए), बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमबीडी) के सहयोग से भागीदार देशों में कंपनियों और बैंकों द्वारा व्यापार वित्त तक पहुंच बढ़ाने के लिए व्यापार वित्त सुविधा की संभावनाएं तलाश सकती हैं। इन सुविधाओं को क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है और स्थानीय बैंक से ऋण सुविधा के लिए जोखिम के प्रतिस्थापन द्वारा स्थानीय जारीकर्ता बैंकों से डीलिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय पुष्टिकर्ता (कंफर्मिंग) बैंकों की जोखिम वहन क्षमता बढ़ाने के लिए गैर-वित्तपोषित गारंटी प्रदान कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए व्यापार वित्त ऋण भी प्रदान किया जा सकता है, जो कंपनी के व्यापार चक्र अवधि के आसपास संरचित हो। यह सुविधा स्थानीय बैंकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में भी सहायता प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, अनुपालन की लागत को कवर करने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा सकती है, जो बैंकों के ऑन-बोर्डिंग से जुड़ी हो सकती है। इस तरह की अलग व्यापार वित्त सुविधाएं जी20 देशों के बीच सहयोग के माध्यम से गठित की जा सकती हैं। यह सुविधा उन देशों के मामले में विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिन्होंने कॉरेस्पॉन्टेंड बैंकिंग संबंधों में तेजी से गिरावट देखी है।

व्यापार वित्त में डेटा अंतर को कम करना: वर्तमान में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण पर डेटा के लिए अभी तक कोई एकल व्यापक स्रोत नहीं है। हालांकि समग्र स्तर पर प्रमुख बाजार प्रतिभागियों द्वारा समय-समय पर जानकारियां प्रकाशित की जाती हैं। तथापि, सुसंगत और समान व्यापार वित्त आंकड़ों की उपलब्धता में सुधार की काफी गुंजाइश बनी हुई है। इस तरह के डेटा नीति निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे और संभावित लिक्विडिटी संकटों के प्रारंभिक चेतावनी विश्लेषण और इसे सुगम बनाने के लिए आवश्यक इनसाइट भी प्रदान कर सकते हैं। समय पर, आधिकारिक व्यापार वित्त आंकड़े तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। जी20 देश व्यापार वित्त डेटा पर संकलन और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा व्यापार वित्त के वास्तविक स्तर की निगरानी करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। साथ ही, अधिक समावेशिता के लिए व्यापार वित्त नीति बनाने और परिचालन में सुधार ला सकते हैं। ■

लोहा और इस्पात उद्योग : बदलते ट्रेंड

– **राहुल मज़ुमदार,** *सहायक महाप्रबंधक*
मयंक खुराना, *उप प्रबंधक*

स्टील यानी इस्पात वैश्विक उद्योगों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक बन गया है। इस्पात काफी हद तक लौह अयस्क पर निर्भर है, जिसका खनन लगभग 50 देशों में किया जाता है और लगभग 98% वैश्विक लौह अयस्क का उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है।

वैश्विक परिदृश्य : लौह और इस्पात

पिछले एक दशक में दुनिया के कच्चे लौह अयस्क भंडार में 170 से 190 बिलियन मीट्रिक टन (बीटी) के बीच उतार-चढ़ाव रहा है। विश्व में कुल लौह अयस्क भंडारों में लौह की औसत मात्रा 47%-49% रही है। देशों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में वैश्विक कच्चे लौह अयस्क भंडार का 28% से अधिक है। इसके बाद ब्राजील (18.9%), और रूस (13.9%) का स्थान है। भारत के कच्चे अयस्क का भंडार 3.1% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ लगभग 5.5 बीटी है, जो दुनिया में सातवां सबसे अधिक है।

इस्पात की बात करें तो, वैश्विक कच्चे इस्पात का उत्पादन 2012 में 1562 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021 में 1951 मीट्रिक टन हो गया, जिसमें 2.5% की एएजीआर दर्ज की गई। वैश्विक कच्चे इस्पात के उत्पादन का बड़ा हिस्सा चीन से आता है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 53% है। भारत 6% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। एक दशक पहले की तुलना में, 2021 में चीन की हिस्सेदारी में लगभग 7% की वृद्धि हुई है।

भारतीय परिदृश्य : लौह और इस्पात

भारत में उच्च विकसित इस्पात विनिर्माण क्षेत्र है, जो कच्चे इस्पात से लेकर मूल्य वर्धित इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के अनुकूल है। यह मुख्य उद्योगों में से एक है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका 2% से थोड़ा अधिक योगदान है।

भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022 में 120 मिलियन टन दर्ज किया गया, जो एक दशक पहले 78.4 मीट्रिक मिलियन टन था। भारतीय इस्पात उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान हर साल औसतन 5% की दर से वृद्धि कर प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

लौह अयस्क उत्पादन की बात की जाए तो भारत का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2021 में 204.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2012 में 168.6 मिलियन टन था। इसमें 3.4% की एएजीआर दर्ज की गई। गोवा और कर्नाटक में खनन पर प्रतिबंध जैसे कारणों से पिछले दशक के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन में अनियमितता रही है।

ओडिशा वित्तीय वर्ष 2021 में 51% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है (वित्तीय वर्ष 2012 में 40%)। इसके बाद छत्तीसगढ़ (18.1%) और कर्नाटक (16.9%) का स्थान है।

लौह और इस्पात का व्यापार

लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स (एचएस 2601)

लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स का वैश्विक निर्यात 2021 में 218 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक दर्ज किया गया, जो 2012 में 128 बिलियन यूएस डॉलर (10% की एएजीआर) था। इसका 50% से अधिक निर्यात ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। हालांकि, आयात मांग और भी अधिक संकेंद्रित है क्योंकि वैश्विक लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स का 70% आयात अकेले चीन द्वारा ही किया जाता है।

लौह अयस्क के व्यापार में भारत का अधिशेष है। देश का निर्यात 2021 में 4 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक दर्ज किया गया, जबकि आयात 0.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब रहा। पिछले दशक के दौरान, भारत ने केवल 2015 में व्यापार घाटा दर्ज किया, क्योंकि कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में विभिन्न प्रतिबंध और उत्पादन सीमाएं थीं। चीन के इस्पात उद्योग के आकार के कारण 2021 में भारत का 80% निर्यात चीन को रहा।

लौह और इस्पात (एचएस 72)

लौह और इस्पात का वैश्विक निर्यात 2012 के 425.9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 557.5 बिलियन यूएस डॉलर (5.7% की एएजीआर) हो गया है। चीन, जापान, जर्मनी, रूस और दक्षिण कोरिया प्रमुख निर्यातक बने हुए हैं।

पिछले दशक के दौरान भारत के लौह और इस्पात के निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जो 2012 के 7.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 21.2 बिलियन यूएस डॉलर (18% की एएजीआर) हो गया। आयात 1.7% की बहुत धीमी दर से बढ़ा। लौह और इस्पात के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2012 की 1.8% से बढ़कर 2021 में 3.8% हो गई। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एफटीए के कारण 2021 में भारत के आयात का पांचवां हिस्सा दक्षिण कोरिया से आया, जबकि 2012 में दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 12 फीसदी थी।

लौह या इस्पात की वस्तुएं (एचएस 73)

लौह या इस्पात की वस्तुओं का वैश्विक निर्यात (एचएस 73) 2012 के 306.1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 359 बिलियन यूएस डॉलर (2.3% की एएजीआर) हो गया। वैश्विक निर्यात के आधे हिस्से में केवल शीर्ष पांच निर्यातकों का योगदान है और उनमें भी अकेले चीन वैश्विक निर्यात में 25% से अधिक का योगदान देता है।

भारत ने एचएस 73 के व्यापार में लगातार अधिशेष बनाए रखा है। भारत एचएस 73 के आयात के लिए मुख्य रूप से चीन (34%) पर निर्भर है, जबकि एचएस 73 के भारत के निर्यात का लगभग 30% संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। एचएस 73 के भारत के आयात स्रोतों में सबसे बड़ा लाभ वियतनाम को हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी 2012 की 0.4% से बढ़कर 2021 में 5.1% हो गई।

उद्योग में नीतिगत परिवर्तन

घरेलू इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2010 में लौह अयस्क लंप्स (10%), फाइन्स (5%) और पेलेट (10%) पर निर्यात लेवी लागू की गई थी। अगले वित्तीय वर्ष में, लौह अयस्क लंप्स, पेलेट और फाइन्स पर सभी ग्रेड में निर्यात टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दी गई थी। अगले दशक के दौरान दरों में विभिन्न संशोधन करने के बाद, भारत सरकार ने लौह अयस्क लंप्स और फाइन्स पर निर्यात शुल्क को बढ़ाकर 50% कर दिया और वित्तीय वर्ष 2023 में पेलेट पर इसे बढ़ाकर 45% कर दिया गया। नवंबर 2022 में, भारत सरकार ने लौह अयस्क लंप्स और 58% एफई सामग्री से नीचे वाले फाइन्स और लौह अयस्क पेलेट पर निर्यात शुल्क वापस ले लिया। लौह अयस्क लंप्स और 58% एफई सामग्री से अधिक वाले फाइन्स के निर्यात के लिए निर्यात शुल्क 30% निर्धारित किया गया। इसके अलावा, कर्नाटक और गोवा में खनन की सीमा और प्रतिबंध जैसे राज्य विशिष्ट नीतिगत परिवर्तन भी हुए हैं।

एक उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन एमएमडीआर (खान और खनिज विकास और विनियमन) अधिनियम, 2015 की शुरुआत है। एमएमडीआर अधिनियम, 2015 के तहत, "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर टोही परमिट (आरपी) की पिछली प्रक्रिया को गैर-अनन्य आरपी से बदल दिया गया था। इसके अलावा, 2021 में पेश किए गए संशोधनों के तहत, कैप्टिव खदानें बाहरी खरीदारों को उत्पादन का 50% तक बेच सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इस्पात उद्योग राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 द्वारा संचालित है, जिसके अनुसार 2030-31 तक 300 एमटीपीए की कच्चे इस्पात की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में तैयार इस्पात की खपत 2030-31 तक 158 किलोग्राम तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्तमान में 61 किलोग्राम है।

चुनौतियां और रणनीति

कोकिंग कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना

भारत में एन्थ्रेसाइट और बिटुमिनस के भंडार 106 बीटी और उप-बिटुमिनस और लिग्नाइट के 5.1 बीटी भंडार हैं। तथापि, "एन्थ्रेसाइट और बिटुमिनस" श्रेणी के तहत, भारत में अधिकांश भंडार बिटुमिनस के हैं। स्टील उत्पादन लागत में कोकिंग कोयले का योगदान लगभग 40-45% है। कोकिंग कोयले के लिए भारत की आयात निर्भरता लगभग 85% है और भारत ने 2030-31 तक इसे 65% तक लाने का लक्ष्य रखा है।

कोकिंग कोयले जैसे कच्चे माल को सुरक्षित करने के लिए पहला कदम आयात स्रोतों में विविधता लाना होगा। वर्तमान में, भारत ऑस्ट्रेलिया पर बहुत अधिक निर्भर है, भारत के कोकिंग कोयले के आयात का लगभग 68% ऑस्ट्रेलिया से आता है।

अतः भारत को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खनन और धुलाई प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, खनन अन्वेषण अधिक कोकिंग कोयला भंडार खोजने में भी सहायक हो सकता है, जो राख सामग्री में कम हो सकता है। कुल मिलाकर, प्रौद्योगिकी में निवेश परिवर्तनकारी हो सकता है और अंततः आयात निर्भरता को कम कर सकता है।

निर्यात में वृद्धि

इस्पात उत्पादों के लिए सुनियोजित निर्यात रणनीति इस उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक बल साबित हो सकती है। वर्तमान में, इस्पात निर्यात मुख्य रूप से घरेलू मांग में गिरावट या बेहतर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, भारत से तैयार इस्पात निर्यात में गैर-मिश्र धातुओं का वर्चस्व है। वित्तीय वर्ष 2022 में 15.5 एमटी तैयार इस्पात निर्यात में से 13.9 एमटी गैर-मिश्र धातुओं का निर्यात रहा। नतीजतन, इस्पात मूल्य श्रृंखला के उच्च छोर पर उत्पादों की तुलना में मूल्य के संदर्भ में निर्यात प्राप्ति कम है।

इसके अलावा, इस्पात क्षेत्र की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। घरेलू स्तर पर, उत्पादित इस्पात किफायती हो सकता है, तथापि निर्यात के लिए आउटबाउंड इस्पात विशेष रूप से उच्च ग्रेड इस्पात या विशेष इस्पात बहुत अधिक निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं है। अंततः, एक स्थिर नीतिगत परिवेश निर्यात की दिशा निर्धारित करने में सबसे महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक हो सकता है। इस्पात पर निर्यात शुल्क जैसे नीतिगत फैसलों से इस्पात निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

लॉजिस्टिक चुनौतियां

भारत में अधिकांश इस्पात संयंत्र बंदरगाहों से दूर हैं, जबकि उन स्थानों के करीब हैं जो कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। तथापि, यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली यात्रा सब्सिडी के कारण भारत में रेलवे की माल ढुलाई लागत अधिक है। इसका एक महत्त्वपूर्ण समाधान यह है कि लौह अयस्क के लिए रेलवे के अंतर्गत माल ढुलाई वर्ग को संशोधित किया जाए। वर्तमान में, लौह अयस्क सहित लौह और इस्पात दोनों 165 श्रेणी के अंतर्गत हैं। तथापि, कोयला श्रेणी 145 के अंतर्गत आता है। लौह अयस्क और इस्पात को श्रेणी 145 के अंतर्गत लाने से माल ढुलाई की दरें कम होंगी और भारतीय इस्पात अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे में मालढुलाई श्रेणी जितनी अधिक होती है, किराया उतना ही अधिक होता है।

इसके अलावा, नए लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। इसमें नए बंदरगाहों को मजबूत करना और विकसित करना, बंदरगाहों और संयंत्रों के बीच समर्पित रेलवे कनेक्टिविटी और औसत गति बढ़ाने के लिए इसे अपग्रेड करना, नए एक्सप्रेसवे का निर्माण आदि शामिल हो सकते हैं।

उद्योग 4.0 और इस्पात उद्योग को एकीकृत करना

इस्पात विनिर्माण में उद्योग 4.0 पद्धतियों को एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दक्ष इस्पात संयंत्रों को बनाने और उत्पादन लागत को कम करने की क्षमता है। मूल रूप से, आईओटी सेंसर का उपयोग संयंत्रों में डेटा एकत्र करने और एआई को डेटा फीड करने के लिए किया जा सकता है। इससे एआई पर्याप्त डेटा उत्पन्न होने के बाद तापमान या हवा के दबाव को समायोजित कर सकेगा। एआई तकनीक मानव त्रुटियों को भी कम करेगी।

हरित इस्पात की ओर कदम बढ़ाना

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लौह और इस्पात उद्योग का लगभग 9-10% हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर, भारत 6.6% की हिस्सेदारी के साथ इस्पात से कार्बन उत्सर्जन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हरित इस्पात की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक लौह और इस्पात उद्योग में हरित हाइड्रोजन का उपयोग है। हालांकि, हरित इस्पात की ओर बढ़ने के लिए नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, हरित इस्पात के लिए उत्पादन की अनुमानित कम लागत के साथ भी, लागत ब्लास्ट फ्यूरेन्स, बेसिक ऑक्सीज़न फ्यूरेन्स तकनीक से काफी ऊपर हो सकती है। इसलिए, समाधानों का पता लगाया जाना चाहिए जहां हरित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन के साथ मिश्रित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार विशेष रूप से हरित इस्पात के उत्पादन के लिए पीएलआई योजना शुरू करने पर भी विचार कर सकती है। ■

भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध

– सारा जॉय, मुख्य प्रबंधक
अल्फिया अंसारी, उप प्रबंधक

वर्ष 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सकल घरेलू उत्पाद मिलाकर विश्व अर्थव्यवस्था का 4.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर (विश्व जीडीपी का 5%) रहा[1]। भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दो सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनके हित और चिंताएं परस्पर अनुरूपी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का वस्तु व्यापार

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल व्यापार 2021 में दोगुना हो गया, जिसमें 2020 की तुलना में आयात में 107% और निर्यात में 97% की वृद्धि दर्ज की गई। 2021 में, निर्यात बढ़ने का मुख्य कारण, खनिज तेलों की बढ़ती मांग और भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हल्के पेट्रोलियम डिस्टिलेट का निर्यात रहा। महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के चलते, द्विपक्षीय व्यापार 2020 में 10.7 बिलियन यूएस डॉलर तक कम हो गया। वहीं, निर्यात 2019 के 3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 में 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इसी अवधि के दौरान, आयात 10.6 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 7.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया।

ऑस्ट्रेलिया को भारत का वस्तु निर्यात

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों में कोरोना वायरस महामारी के बाद अच्छा रुख दिखाई दिया है। 2021 में दोनों के बीच कुल व्यापार बढ़कर 22 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया, जिसमें 2020 की तुलना में 106% की वृद्धि दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया 2021 में भारत का 17वां सबसे बड़ा आयातक रहा और जिसमें भारत के कुल निर्यात में इसकी 1.8% की हिस्सेदारी रही।

ऑस्ट्रेलिया को भारत से पारंपरिक रूप से खनिज ईंधन और तेलों का निर्यात किया जाता रहा है। 2021 में भारत से ऑस्ट्रेलिया को कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं चीजों का रहा। इसके बाद प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती और रत्नों (ऑस्ट्रेलिया को भारत के कुल निर्यात का 5.3%), फार्मासूटिकल उत्पाद (5%), मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (3.5%), लोहे या स्टील की वस्तुएं (3.2%) और विद्युत मशीनरी और उपकरण (2.8%) शामिल रहे।

ऑस्ट्रेलिया से भारत का वस्तु आयात

वर्ष 2021 में, ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए 11वां सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा। भारत के कुल आयात में इसकी 2.6% की हिस्सेदारी रही। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आयात किए जाने वाले उत्पादों की बात की जाए तो 2021 में खनिज ईंधन और तेल (एचएस -27) की हिस्सेदारी ऑस्ट्रेलिया से भारत के कुल आयात में 75.6% की रही। एचएस-27 के तहत 6 अंकों के स्तर पर, 2021 में भारत द्वारा सबसे अधिक आयातित वस्तु कोयला रहा, जिसका आयात 11.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इस उत्पाद श्रेणी के तहत आयात 2016 में 4.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 11.4 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाने वाली अन्य प्रमुख वस्तुओं में प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती या रत्न (ऑस्ट्रेलिया से भारत के कुल आयात का 7.6%), अयस्क, स्लैग और राख (5.3%) और अकार्बनिक रसायन (2.9%) शामिल रहे।

भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापार में वर्तमान बाधा

हाल ही में 29 दिसंबर, 2022 को एआई-ईसीटीए लागू होने के बाद से ऑस्ट्रेलिया पर प्रभावी रूप से लागू टैरिफ एमएफएन टैरिफ के समान है।

ऑस्ट्रेलिया से भारत के आयात पर टैरिफ

यह प्रभावी रूप से लागू ऐसा टैरिफ है, जिसका सामना ऑस्ट्रेलियाई निर्यातकों को भारत में निर्यात करते समय करना पड़ता है। उत्पादों की 159 श्रेणियां (6-अंकीय एचएस कोड पर) हैं, जिन पर प्रभावी रूप से 0% की टैरिफ दर लागू है। इस श्रेणी में 2021 में कुल आयात 286.6 मिलियन यूएस डॉलर का रहा और यह 2021 में ऑस्ट्रेलिया से भारत के कुल आयात का केवल 1.9% है। 01%-03% की प्रभावी लागू टैरिफ दर के अंतर्गत 25 उत्पाद श्रेणियां हैं, जो 2021 में कुल आयात का उच्चतम 80.7% रहीं और इनका आयात 12.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। 03%-15% की लागू टैरिफ दर के अंतर्गत 1,118 उत्पाद श्रेणियां हैं और 2021 में इनका आयात कुल आयात का 16.3% रहा, जो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

इस प्रकार संचयी रूप से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से होने वाले 98.9% भारतीय आयातों को 15% से कम या इसके समान प्रभावी रूप से लागू टैरिफ दर का सामना करना पड़ता है। 2021 में, 246 उत्पाद श्रेणियों को 1.1% की कुल आयात हिस्सेदारी के साथ 15%-150% के प्रभावी रूप से लागू टैरिफ का सामना करना पड़ा। एचएस 6-अंकीय स्तर पर 13 उत्पाद श्रेणियां हैं जो मुख्य रूप से पेय पदार्थों (एचएस-22) और ऑटोमोबाइल (एचएस-87) से संबंधित हैं, जिनमें प्रभावी रूप से लागू टैरिफ 100% से अधिक है।

भारत से ऑस्ट्रेलिया के आयात पर टैरिफ

एक विकसित क्षेत्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया में न्यून एमएफएन टैरिफ है और इस प्रकार वह अपने मित्र देशों के साथ मुक्त और आसान व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत की तुलना में, ऑस्ट्रेलिया के मामले में प्रभावी रूप से लागू टैरिफ कम है, क्योंकि यह एक विकसित देश है। यहां 2021 में उत्पादों की 1,046 श्रेणियां (6-अंकीय एचएस कोड वाली) रहीं, जिनका आयात 3.8 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और जिन पर प्रभावी रूप से 0% की टैरिफ दर लागू है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत से किए गए आयात के आधे से अधिक (59.6%) उत्पाद इसी श्रेणी के रहे। 1%-3% के प्रभावी रूप से लागू टैरिफ के अंतर्गत 189 उत्पाद श्रेणियां रहीं, जिनकी 2021 में आयात में हिस्सेदारी 6.7% रही और 425 मिलियन यूएस डॉलर का आयात किया गया। इसके बाद, ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत से आयात की जाने वाली 1,588 उत्पाद श्रेणियां रहीं, जिनके लिए 3%

[1] वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2022 .

से 5% की प्रभावी रूप से लागू टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है और जिनमें आयात 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

भारत द्वारा किए गए गैर-टैरिफ उपाय

एकीकृत व्यापार आसूचना पोर्टल (आई-टीआईपी), डब्ल्यूटीओ से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जून 2022 तक भारत ने डब्ल्यूटीओ सदस्यों (ऑस्ट्रेलिया सहित) पर 1,029 एनटीएम लगाए हैं। साथ ही, भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर द्विपक्षीय रूप से भी एनटीएम लगाए गए हैं। 1,029 एनटीएम में से, 362 को लागू किया गया और 667 प्रवर्तित किए गए[2]। एसपीएस और टीबीटी सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एनटीएम में से हैं, जिनमें 276 एसपीएस (32 लागू और 244 प्रवर्तित) और 273 टीबीटी (7 लागू और 266 प्रवर्तित) हैं। भारत द्वारा एंटी-डंपिंग उपायों को भी अपनाया गया है। इसके बाद जून 2022 तक मात्रात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर), काउंटरवेलिंग उपायों (सीवी), राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई), सुरक्षा (एसजी) और टैरिफ-दर कोटा (टीआरक्यू) उपायों के माध्यम से संरक्षण के उपाय किए गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए गैर-टैरिफ उपाय

जून 2022 तक, ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूटीओ सदस्यों (भारत सहित) के लिए 1,046 एनटीएम हैं। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत पर द्विपक्षीय रूप से भी एनटीएम लगाए गए हैं। 1,046 एनटीएम में से, 326 को लागू किया गया था और 720 प्रवर्तित किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के आयात एनटीएम ज्यादातर तकनीकी उपाय हैं, जो तकनीकी विनियमों और मानकों के अनुपालन के लिए तकनीकी विनियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। एसपीएस और टीबीटी उपाय अधिकांशतः इस्तेमाल किए गए एनटीएम में से हैं, जिनमें 514 एसपीएस और 239 टीबीटी उपाय हैं। इनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने एनटीएम के तहत एंटी-डंपिंग (एडीपी), काउंटरवेलिंग (सीवी), मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर), टैरिफ-रेट कोटा (टीआरक्यू), राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) और निर्यात सब्सिडी (एक्सएस) उपाय भी अपनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का सेवा व्यापार

भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों विश्व स्तर पर प्रमुख सेवा व्यापार देश हैं। ऑस्ट्रेलिया 2021 में वैश्विक स्तर पर जहां 28वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक रहा, वहीं भारत 8वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक रहा। 2021 में, आयात के मामले में, ऑस्ट्रेलिया 30वां सबसे बड़ा वैश्विक सेवा आयातक रहा, वहीं भारत 10वें स्थान पर रहा।

ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के सुदृढ़ सेवा व्यापार संबंध हैं। 2020 में, ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक सेवा निर्यात में 9.6% की हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक रहा और ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक सेवा आयात में 3.5% की हिस्सेदारी के साथ 9वां सबसे बड़ा आयात आपूर्तिकर्ता रहा।

भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया का कुल सेवा व्यापार 2010 के 4.1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 में 6.1 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। हालांकि, महामारी और संबंधित अनिश्चितता के कारण, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के सेवा व्यापार में 2019 की तुलना में 2020 में 15.2% की गिरावट आ गई। 2019 में यह 7.2 बिलियन यूएस डॉलर के अपने चरम पर था। 2010-2020 के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार भारत के साथ व्यापार अधिशेष बनाए रखा, जो 2020 में 3.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

भारत को ऑस्ट्रेलिया का सेवा निर्यात

भारत 2020 में ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरा सबसे बड़ा सेवा निर्यात गंतव्य रहा। पिछले दशक में, भारत को ऑस्ट्रेलिया का सेवा निर्यात लगातार बढ़ा है। यह 2010 के 3.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2020 में 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को सेवाओं के निर्यात का उच्चतम स्तर पर (5.3 बिलियन यूएस डॉलर) दर्ज किया गया। हालांकि, 2019-2020 के दौरान एक ही वर्ष में निर्यात में 9.4% की गिरावट आई।

वर्ष 2020 में, भारत को ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात में यात्रा खंड की सर्वाधिक 92.5% की हिस्सेदारी रही। ऑस्ट्रेलिया से अन्य निर्यातों में व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं और दूरसंचार, सूचना और कंप्यूटर सेवाएं शामिल रहीं।

भारत से ऑस्ट्रेलिया का सेवा आयात

वर्ष 2020 में, ऑस्ट्रेलिया के कुल सेवा आयात में भारत की 3.5% की हिस्सेदारी रही और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए 9वां सबसे बड़ा सेवा आपूर्तिकर्ता रहा। 2010-2020 के दौरान, भारत से कुल सेवा आयात बढ़ा। 2010 में यह जहां 796 मिलियन यूएस डॉलर का था, वहीं 2020 में बढ़कर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। भारत से ऑस्ट्रेलिया का सेवा आयात 2019 में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर के अपने सर्वोच्च स्तर पर रहा। महामारी के कारण संपर्क गहन क्षेत्रों सहित सेवा क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और इस प्रकार 2019 और 2020 के बीच एक वर्ष में अकेले भारत से आयात में लगभग 26.3% की गिरावट आई।

भारत से ऑस्ट्रेलिया के कुल सेवा आयात में मुख्य रूप से वाणिज्यिक सेवाएं शामिल हैं, जिनमें सरकारी सेवाओं का हिस्सा नगण्य है। भारत से ऑस्ट्रेलिया के सेवा आयात का 38% हिस्सा दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का है। इसके बाद अन्य व्यावसायिक सेवाओं और यात्रा खंड का स्थान है, जिनका हिस्सा 2020 में भारत से कुल सेवा आयात का क्रमशः 30.5% और 24.2% रहा।

ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार करार

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में ईसीटीए करार पर हस्ताक्षर किए थे। यह करार 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई बाजार के आकार और दोनों देशों के बीच हाल ही में व्यापार वृद्धि को देखते हुए एआई-ईसीटीए भारत के लिए एक ऐतिहासिक करार है।

ऑस्ट्रेलियाई आयात पर भारत द्वारा टैरिफ कटौती की पेशकश

6 अंकों के एचएस-कोड वाले 1,595 उत्पाद हैं, जिन्हें सीमा शुल्क में कमी या शुल्क हटाने की किसी भी प्रतिबद्धता से बाहर रखा गया है। 2021 में भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से इन उत्पादों का आयात 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और भारत के कुल आयात में इनका हिस्सा 11.2% रहा। शुल्क कटौती की प्रतिबद्धता

[2] प्रवर्तित तिथि वह तारीख है जब तैयार किया जा रहा उपाय अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों को बताया जाता है; एसपीएस और टीबीटी में यह वह तारीख है जब उपाय डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अन्य सदस्यों को वितरित किया जाता है। एडी, सीवी और एसजी में, जांच शुरू करने की तिथि भी वह तारीख है जब प्रभावित सदस्य को प्रवर्तन के बारे में सूचित किया जाता है। कृषि एनटीएम में, प्रवर्तन लागू नहीं है। एंटी-डंपिंग, काउंटरवेलिंग और संरक्षण उपायों के मामले में कोई उपाय लागू होने पर ही लागू होता है; जबकि एसपीएस और टीबीटी के लिए यह अधिसूचित किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

से बाहर रखे गए इन उपादों के अंतर्गत आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में अर्द्धविनिर्मित रूप वाला सोना (एचएस -710812) है, जिस पर 12.5% का टैरिफ लागू है और 2021 में इसका आयात 1.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

6 अंकों के एचएस कोड वाली 1,590 उत्पाद श्रेणियां हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से आने वाली वस्तुओं पर ऐसी टैरिफ लाइनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन पर सीमा शुल्क को 3, 5, 7 या 10 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में कम या समाप्त कर दिया जाएगा। 2021 में कुल आयात में इन उत्पादों का हिस्सा 2.1% रहा, जो 320 मिलियन यूएस डॉलर का रहा।

इसी तरह, 6 अंकों के एचएस कोड वाली 2,196 उत्पाद लाइनें हैं, जिनके लिए एआई-ईसीटीए के लागू होने की तारीख से शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत आयात 12.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से किए जाने वाले कुल आयात में इसकी हिस्सेदारी 85.3% की रही। वर्ष 2021 में, "एलिमिनेशन एट फोर्स" श्रेणी के तहत प्रमुख आयात कोकिंग कोल (एचएस-270119) रहा। इसके लिए 1% की दर पर टैरिफ लगाया गया और इसका आयात 11.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। तांबा अयस्क और कन्संट्रेट्स (एचएस-260300) पर वर्तमान में 2.5% का टैरिफ लागू है, जिनका आयात 504.4 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। एल्युमिना, कैलसाइन्ड (एचएस-281820) पर वर्तमान में 6.25% का टैरिफ लागू है, जिनका आयात 400.7 मिलियन यूएस डॉलर का रहा।

भारतीय आयात पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा टैरिफ कटौती की पेशकश

भारत ने एआई-ईसीटीए के तहत शुल्क समाप्त करने के संबंध में ऑस्ट्रेलिया से आकर्षक रियायतें हासिल की हैं। इस करार के तहत, ऑस्ट्रेलिया द्वारा 5 वर्षों में 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त किए जाने हैं। 6 अंकों के एचएस कोड वाली 2,771 उत्पाद श्रेणियों के लिए टैरिफ एआई-ईसीटीए लागू होने की तारीख से समाप्त हो जाएंगे। भारत से ऑस्ट्रेलिया के कुल आयातों का 97.4% हिस्सा इन्हीं उत्पादों का है और 2021 में जिनका आयात 6.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है।

ऐसे उत्पाद, जिन पर करार के प्रवर्तन की तारीख से टैरिफ समाप्त कर दिए जाएंगे, उनके तहत सबसे बड़ी आयातित कमोडिटी पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज, प्रिपेरेशंस (एचएस- 271000) से प्राप्त तेल हैं, जिनका आयात 2.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। "एलिमिनेशन एट फोर्स" श्रेणी के तहत अन्य प्रमुख आयातों में मेडिकामेंट (एचएस-300490), हीरे (आभूषण) काम किए हुए, किन्तु माउंटेड या सेट न किए हुए (एचएस-710239) और आभूषण और चांदी को छोड़कर कीमती धातु के हिस्से (एचएस-711319) शामिल रहे।

8 अंकों के एचएस कोड वाले उत्पादों की 113 लाइनें हैं, जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया इस करार के लागू होने की तारीख से पांच समान वार्षिक किस्तों में टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा। भारत से ऑस्ट्रेलिया के आयात में इन उत्पादों का 2.6% हिस्सा है, जिनका आयात 168.5 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। "चरणबद्ध तरीके से शुल्क हटाने" की श्रेणी के तहत शीर्ष आयातों में ग्राइंडिंग मिलों के लिए बॉल, लौह या इस्पात, कास्ट (एचएस-732591), पाइप, 406.4 मीटर से कम व्यास वाले आयरन स्टील (एचएस-730630), लोहे या इस्पात की वस्तुएं (एचएस-732690) और टेबल किचन वस्तुएं, पार्ट्स, स्टेनलेस स्टील (एचएस-732393) शामिल हैं।

सेवाओं में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धताएं

ऑस्ट्रेलिया ने सेवाओं में जीएटीएस/एफटीए प्लस प्रतिबद्धता शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, ऑडियो विज़ुअल सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं, शिक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रोफेशनल सेवाओं (विधिक सेवाओं, लेखा, कराधान, वास्तुकला सेवाओं, इंजीनियरिंग, एकीकृत इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन और परिदृश्य वास्तुकला सेवाओं, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा सेवाओं, नर्सिंग सेवाओं आदि), पर्यावरण सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन और यात्रा से संबंधित सेवाओं, परिवहन सेवाओं आदि जैसे भारत के हित के सेवा क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रतिबद्धताएं जताई गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमा पार सेवाओं की आपूर्ति और वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से डिलीवर की गई सेवाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा वाणिज्यिक रूप से सार्थक बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं प्रदर्शित की गई हैं।
- भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन के बाद 4 साल तक कामकाजी वीजा।
- इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी, कॉन्ट्रैक्चुअल सेवा आपूर्तिकर्ताओं और स्वतंत्र एक्ज़ीक्यूटिव्स के लिए उदार अस्थायी प्रवेश और अस्थायी प्रवास (4 साल तक) की प्रतिबद्धताएं।
- कॉन्ट्रैक्चुअल सेवा आपूर्तिकर्ताओं के रूप में प्रवेश करने वाले योग्य, पेशेवर भारतीय पारंपरिक शेफ और योग प्रशिक्षकों के लिए प्रति वर्ष 1800 का कोटा।
- युवा प्रोफेशनलों के लिए काम और अवकाश वीजा व्यवस्था।

ऑस्ट्रेलिया ने बिजनेस विजिटर्स (बीवी), इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्चुअल सेवा आपूर्तिकर्ता, स्वतंत्र एक्ज़ीक्यूटिव्स और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए इंस्टॉलर्स तथा सर्विसर्स के लिए बाजार पहुंच को सुगम बनाने की पेशकश की है। इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों द्वारा पति/पत्नी और आश्रितों के लिए प्रवेश, ठहरने और कार्य अधिकारों के संबंध में भी प्रतिबद्धताएं प्रदर्शित की गई हैं।

सेवाओं में भारत की प्रतिबद्धताएं

ऑस्ट्रेलिया ने जहां भारत को 135 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है, वहीं भारत ने लगभग 103 उप-क्षेत्रों (जीएटीएस-36) में प्रतिबद्धताएं प्रस्तावित की हैं। इनमें 31 उप-क्षेत्रों में एमएफएन का दर्जा दिया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित 11 सेवा श्रेणियां शामिल हैं- "आईटी और संचार सेवाएं", "व्यवसाय सेवाएं", "निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं", "वितरण सेवाएं", "शैक्षणिक सेवाएं", "पर्यावरण सेवाएं", "वित्तीय सेवाएं", "स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएं", "पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं", "मनोरंजक सांस्कृतिक और खेल सेवाएं" तथा "परिवहन सेवाएं"।

भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया के हितों वाले व्यवसाय सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, शैक्षणिक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्धताओं की पेशकश की गई है। भारत 6 वर्षों में निगेटिव शेड्यूल अप्रोच लागू करेगा। दोनों देश प्रोफेशनल सेवाओं और अन्य लाइसेंस प्राप्त/विनियमित व्यवसायों की पारस्परिक मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत प्रावधानों पर सहमत हुए हैं। ■

भारतीय रसायन उद्योग: विकास क्षमता की संभावनाएं

– **राहुल मजुमदार,** *सहायक महाप्रबंधक*
साक्षी गर्ग, *उप प्रबंधक*

रसायन उद्योग आधुनिक वैश्वीकृत विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक रहा है, जो कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, वायु, पानी, धातुओं और खनिजों जैसे कच्चे माल को हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक विविध तैयार उत्पादों में परिवर्तित करता है। उर्वरकों, कीटनाशकों, एलईडी लाइटिंग और अन्य कृषि रसायन उत्पादों जैसे तैयार उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने के अलावा, यह उद्योग सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक और जल रसायन विज्ञान जैसी अन्य विनिर्माण गतिविधियों के लिए भी महत्त्वपूर्ण इनपुट का उत्पादन करता है, जो दुनियाभर के उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को लाभान्वित करते हैं।

वैश्विक रसायन उद्योग

वैश्विक रसायन उद्योग का राजस्व 2006 और 2021 के दौरान 2.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से दोगुने से अधिक होकर 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया है। चीन 2020 में रसायनों की वैश्विक बिक्री में 44.6% की हिस्सेदारी के साथ रसायन विनिर्माण में अग्रणी रहा। यूरोपीय संघ 570.0 बिलियन यूएस डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका 486.6 बिलियन यूएस डॉलर, जापान 164.5 बिलियन यूएस डॉलर, दक्षिण कोरिया 116.5 बिलियन यूएस डॉलर और भारत 105.1 बिलियन यूएस डॉलर अन्य अग्रणी देश हैं। उल्लेखनीय है कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद, विकासशील देशों में रसायन विनिर्माण ने गति पकड़नी शुरू कर दी है। इससे एशिया दुनिया के रसायन विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना शुरू हो गया है।

भारत में हाल के रुझान

भारतीय रसायन उद्योग एक बुनियादी रासायनिक उत्पादक से एक अभिनव उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021 में कुल सकल मूल्य वर्धन में "रसायन और रासायन उत्पाद" क्षेत्र का योगदान 1.4% और कुल विनिर्माण उत्पादन का योगदान 9.6% रहा। विशेष रूप से, यह उद्योग रोजगार सृजन का एक समृद्ध स्रोत भी है, जिसमें एमएसएमई का हिस्सा 25%-30% है।

प्रमुख रसायनों की स्थापित क्षमता और उत्पादन

भारत में प्रमुख रसायनों की स्थापित क्षमता वित्तीय वर्ष 2021 में 156 लाख टन रही। जबकि उत्पादन 112.42 लाख टन रहा। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, भारत में उत्पादित प्रमुख रसायनों में से लगभग 70% क्षार रसायन रहे। कार्बनिक रसायनों का उत्पादन 17% रहा, जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा रहा। इसके बाद अकार्बनिक रसायन (9%), रंजक और पिगमेंट (3%), और कीटनाशक (2%) रहे। अकार्बनिक रसायनों के अलावा, अन्य सभी प्रमुख रसायन क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई।

रासायनिक उत्पादों में भारत का व्यापार

रसायन भारत के निर्यात बास्केट का एक अभिन्न हिस्सा है। 2021 में कुल निर्यात में इसकी 8% की हिस्सेदारी रही। 2017-2021 की अवधि के दौरान, रसायनों के निर्यात में 12.8% की अच्छी एएजीआर दर्ज की गई। हालांकि, भारत लंबे समय से रसायनों का शुद्ध आयातक बना हुआ है। 2017-21 के दौरान रसायनों के आयात में वृद्धि हुई है और 14.1% की एएजीआर दर्ज की गई। 2021 में भारत के आयात बास्केट का लगभग 5% हिस्सा रसायनों का रहा। नतीजतन, रसायनों में भारत का व्यापार घाटा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है।

भारत का रसायन निर्यात 2017 के 20.4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 31.9 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। 2021 में 21.2 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात के साथ कार्बनिक रसायन सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली श्रेणी में शामिल रहे। निर्यात में 12.7% की अच्छी एएजीआर दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, अन्य श्रेणियों में भी अच्छी निर्यात वृद्धि दर्ज की गई। 2021 में अकार्बनिक रसायनों का निर्यात 13.3% बढ़कर 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया; टैनिंग या रंगाई अर्क 9.9% बढ़कर 3.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया; और 17.2% की एएजीआर के साथ कीटनाशकों, कृन्तकनाशकों आदि का निर्यात 2021 में 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

इसी अवधि (2017-2021) के दौरान, भारत का रसायन आयात 26.8 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 41.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। आयातों का अधिकांश हिस्सा कार्बनिक रसायनों का रहा (66%) और इनका आयात 2017 के 18 बिलियन यूएस डॉलर से 9.3 बिलियन यूएस डॉलर की वृद्धि के साथ 27.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। 2021 में, अकार्बनिक रसायनों में 9.6 बिलियन यूएस डॉलर के आयात के साथ 17.6% की उच्चतम एएजीआर दर्ज की गई। टैनिंग या रंगाई के अर्क और कीटनाशकों, कृन्तकनाशकों आदि का आयात 2021 में क्रमशः 2.5 बिलियन यूएस डॉलर और 1.9 बिलियन यूएस डॉलर के आयात के साथ क्रमशः 9.1% और 10.6% की एएजीआर से बढ़ा।

कुल मिलाकर, इस उद्योग के लिए, व्यापार घाटा 2021 में 9.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2017 में 6.4 बिलियन यूएस डॉलर के घाटे से

अधिक रहा। व्यापार घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण अकार्बनिक रसायनों के बढ़ते आयात को माना जाता है, जिसके कारण व्यापार घाटा 2017 के 4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2021 में 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। यह घाटा मुख्य रूप से चीन, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से आयात के चलते रहा। इन ट्रेंड्स से पता चलता है कि निर्यात में वृद्धि रसायनों के बढ़ते आयात के अनुरूप नहीं है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, इस उद्योग को घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

रसायन उद्योग की विकास क्षमता तलाशना

भारत में रसायन उद्योग ने मूल्य सृजन की दिशा में लगातार योगदान दिया है और विश्व स्तर पर इसकी मजबूत उपस्थिति है। उपयोगकर्ता उद्योगों में कम प्रति व्यक्ति खपत और कम पैठ लंबी अवधि में विशाल अप्रयुक्त अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, रसायनों में बढ़ते व्यापार घाटे के साथ, प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान विकसित कर आयातों का प्रतिस्थापन कर रसायन उद्योग को बढ़ाया जा सकता है।

नए बाजारों की तलाश

रसायनों की मांग अत्यधिक डायनैमिक है। किसी क्षेत्र में परिपक्व उत्पाद किसी दूसरे क्षेत्र में अभिनव उत्पाद हो सकते हैं। इस प्रकार रसायनों के विभिन्न खंडों में उच्चतम आयात वृद्धि वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है। अकार्बनिक रसायनों के लिए, शीर्ष बढ़ते बाजार पोलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और थाईलैंड हैं। इन बाजारों को भारत के मौजूदा निर्यात का हिस्सा इनके वैश्विक आयातों में मामूली है। कार्बनिक रसायनों के लिए, भारत के लिए आयरलैंड, तुर्की, रूस, स्पेन और बेल्जियम को निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं है। टैनिंग या रंगाई अर्क में, वियतनाम, बेल्जियम, पोलैंड, नीदरलैंड और चीन आकर्षक बाजार हैं। कृषि रसायनों के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील जैसे उच्च वृद्धि वाले बाजारों के आयात में भारत के निर्यात का पहले से ही उल्लेखनीय हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

क्षमता अभिवृद्धि के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन को सुगम बनाना

इस क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। यह आवश्यकता विशेष रूप से पिछले दशक में चीन से बढ़ते रसायनों के आयात के संदर्भ में और बढ़ जाती है। इसके अलावा, मौजूदा क्षमता का इष्टतम उपयोग भी आवश्यक है। अकार्बनिक रसायनों की क्षमता की उपयोग दर 63% है। यह देखते हुए कि इस खंड में निर्यात में मध्यम वृद्धि के साथ-साथ आयात बढ़ा है, वर्तमान क्षमता का इष्टतम उपयोग करने की आवश्यकता है। कीटनाशकों और रंगों तथा पिगमेंट्स में भी क्षमता उपयोग न्यून है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में अधिक एकीकरण की आवश्यकता

चीन में रसायन और फार्मासूटिकल उत्पादों के लिए पिछले दो दशकों से उच्च फॉरवर्ड लिंकेज (60% से अधिक) रहा है और भारत के लिए यह 50% से नीचे रहा है। इसके अलावा, रसायन और फार्मासूटिकल उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्रियों के लिए भारत की निर्भरता चीन पर (बैकवर्ड लिंकेज) बढ़ती रही है। 2012-2021 के दौरान, दुनिया के बाकी हिस्सों से भारत का रसायन आयात जहां 8.3% की एएजीआर से बढ़ा, वहीं चीन से आयात में 11.8% की एएजीआर दर्ज की गई, जो 2021 में भारत के रसायन आयात का लगभग 35% रहा। आयात निर्भरता को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जीवीसी में भारत के एकीकरण को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही, घरेलू विनिर्माताओं को उत्पादन के विभिन्न चरणों में विशेषज्ञता प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए।

अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना

थोक उत्पाद खंड में, रसायन उद्योग को उत्पादन लागत में कमी के उद्देश्य से प्रक्रियागत नवाचार करना चाहिए। इसके अलावा, इस उद्योग को विशेष उत्पाद विकास में अग्रणी तकनीकी संसाधनों में निवेश करने की आवश्यकता है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, रसायन उद्योग के लिए अधिक समर्पित क्षेत्रीय क्लस्टर बनाए जाने चाहिए। इसी तरह, केमिकल इंजीनियरिंग पर केंद्रित अधिक विश्वविद्यालयों को नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए।

रसायन उद्योग में एसएमई के लिए फंड

विदेशों में उल्लेखनीय बाजार क्षमता के साथ, लघु और मध्यम उद्यमों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि विदेशी बाजारों का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार, सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की तर्ज पर या सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए उपलब्ध त्वरित मूल्यह्रास के प्रावधान के आधार पर एक उपयुक्त निधि का गठन किया जा सकता है। इस निधि का उपयोग डिजाइन, पेटेंट, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

भारत में स्थिरता और हरित रसायन विज्ञान की ओर बढ़ना

हरित रसायन विज्ञान (ग्रीन केमिस्ट्री) का लक्ष्य सबसे सुरक्षित और दक्ष तरीकों से बेहतर और सुरक्षित रसायन तैयार करना और इसके विनिर्माण में होने वाले अपशिष्ट को कम करना है। ग्रीन केमिस्ट्री के उत्थान में तेजी लाने के लिए, ग्रीन केमिस्ट्री एनेबलर्स, मार्केट ड्राइवर्स और बाधाओं की व्यापक समझ बनाते रहना महत्त्वपूर्ण है। ग्रीन केमिस्ट्री की आपूर्ति और इसकी मांग को बढ़ाने वाली अनुकूल संघीय नीतियों का सहयोग मिलना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना अहम फंडिंग और प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं का हल करना। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

सौजन्य: ऋण व्यवस्था समूह

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत इंडिया एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातकों को कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के कम से कम 75% के माल एवं सेवाओं का आयात भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाभार्थी देशों में भारत की राजनीतिक ख्याति को बढ़ाने का काम भी किया है। ऋण-व्यवस्थाएं भारत की बढ़ी आर्थिक मजबूती के साथ-साथ इन ऋण-व्यवस्थाओं के प्राप्तकर्ता देशों में बुनियादी ढांचागत विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता को वैश्विक पटल पर लाने में भी मदद करती हैं। ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों के ऐसे बाजारों में जरूरी माल और सेवाओं के निर्यात में भी मददगार हैं, जहां भारत की मौजूदगी न के बराबर है। भारतीय निर्यातक इंडिया एक्ज़िम बैंक से अपने माल के लिए पात्र मूल्य हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का रिकोर्स नहीं रहता। बैंक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन/ सेवाओं के प्रावधान के एवज में किया जाता है। भारतीय निर्यातक माल के शिपमेंट पर इंडिया एक्ज़िम बैंक के जरिए पूरा भुगतान ले सकते हैं और इसमें उन्हें क्रेता या क्रेता देश से जुड़े किसी तरह के जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता।

ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों को या उनकी नामित एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, ताकि उन देशों में क्रेता भारत से माल और सेवाओं का आस्थगित भुगतान शर्तों पर आयात कर सकें। बैंक द्वारा यथा 26 सितंबर, 2023 को अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 27.98 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 274 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने जनवरी से मार्च 2023 की अवधि के दौरान, भारत सरकार के सहयोग से नीचे उल्लिखित अनुसार, एक ऋण-व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए :

क्यूबा सरकार द्वारा नामित एजेंसी, बैंको एक्सटीरियर दे क्यूबा (बीईसी) को 2.63 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था यथा 31 दिसंबर, 2021 को ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत अतिदेय की पुनर्संरचना के लिए प्रदान की गई।

- उपरोक्त ऋण-व्यवस्था पर हस्ताक्षर के साथ ही इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा बीईसी को भारत सरकार के सहयोग से अब तक 349.69 मिलियन यूएस डॉलर की कुल 7 ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान की जा चुकी हैं। क्यूबा को प्रदान की गई इन ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत बल्क ब्लेंडिंग उर्वरक संयंत्र, एक इंजेक्टेबल प्लांट के आधुनिकीकरण, 51 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई की स्थापना, 50 मेगावाट के को-जेनरेशन विद्युत संयंत्र की स्थापना, 75 एमडब्ल्यूपी के फोटोवोल्टिक सोलर पार्कों की स्थापना और भारत से चावल की खरीद संबंधी परियोजनाओं को कवर किया गया है। इनमें से 2.71 मिलियन यूएस डॉलर की एक परियोजना, "क्यूबा में बल्क ब्लेंडिंग उर्वरक संयंत्र" पूरी हो गई है और अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें–

श्री दीपक कुजूर
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात–आयात बैंक
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर–1, 7वीं मंजिल, एड्जेसेंट रिंग रोड
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली–110023
फोन–(011) 24607700
ई–मेलः eximloc@eximbankindia.in ■

दास्तान–ए–कामयाबी

मॉरीशस सरकार को इंडिया एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार समर्थित 465 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने मॉरीशस सरकार को भारत सरकार समर्थित 465 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की थी। इस ऋण-व्यवस्था करार पर 27 मई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह ऋण-व्यवस्था विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई थी।

परियोजना का विवरण :

कॉन्ट्रैक्ट पर न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी लिमिटेड और मॉरीशस सरकार के स्थानीय सरकार एवं आपदा जोखिम प्रबंधन मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और कॉन्ट्रैक्ट को 26 अक्टूबर, 2020 को ऋण-व्यवस्था में शामिल किया गया।

परियोजना के कार्यक्षेत्र में 3 जल / फोम टेंडरों सहित 20 अग्निशमन और रेस्क्यू वाहनों की आपूर्ति, टेस्टिंग और कमिशनिंग शामिल था।

परियोजना की कुल लागत - **6,432,434 यूएस डॉलर**

परियोजना **8 सितंबर, 2022** को सफलतापूर्वक पूरी हो गई। ■

बीती तिमाही की गतिविधियां

सौजन्य: **कॉर्पोरेट संचार समूह**

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने बेंचमार्क साइज़ के संपोषी बॉन्ड के साथ खोले भारतीय बाज़ार

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने 10 जनवरी, 2023 को 144ए/रेग-एस फॉर्मैट में 1 बिलियन यूएस डॉलर का 10 वर्षीय बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया। बैंक ने यह बॉन्ड अपने पर्यावरणीय सामाजिक गवर्नैंस (ईएसजी) फ्रेमवर्क के तहत जारी किया है। इसके साथ ही इंडिया एक्ज़िम बैंक 2023 में बाज़ारों को डॉलर के लिए खोलने वाला और संपोषी बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला निर्गमकर्ता रहा। इंडिया एक्ज़िम बैंक को साल की अच्छी शुरुआत और प्रलक्षित बाजार के मद्देनज़र इंट्राडे एक्ज़ीक्यूशन के साथ मजबूत मांग का लाभ मिला। बैंक ने प्रारंभिक मूल्य से 30 बीपीएस की टाइटनिंग के साथ सीटी 10+190 बीपीएस की दर पर यह बॉन्ड जारी किया, जो बैंक की सेकेंडरीज़ और कर्व के फेयर वैल्यू पॉइंट के समान रहा।

इस संपोषी बॉन्ड की निवल प्राप्य राशि को बैंक के ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो फ्रेमवर्क में प्रमुख हरित और सामाजिक श्रेणियों के अनुरूप हैं। इनमें अक्षय ऊर्जा; स्वच्छ परिवहन; आवश्यक सेवाओं और मूलभूत बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर; किफायती आवास; और संधारणीय जल तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। संपोषी बॉन्ड से मिलने वाली इस राशि के इस्तेमाल की वार्षिक रिपोर्टिंग बाह्य सत्यापन पर निर्भर करेगी।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने अपनी ईएसजी पहलों को बढ़ाने के लिए पारदर्शी तरीके से और अपने स्टेकहोल्डरों से संवाद स्थापित करते हुए निरंतर काम किया है। बैंक ने हरित, सामाजिक अथवा संपोषी बॉन्ड / ऋणों के लिए एक ईएसजी फ्रेमवर्क लागू किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने गत वर्ष बोर्ड से अनुमोदित अपनी ईएसजी नीति संपोषी विकास / उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के लिए बैंक की पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नैंस नीति को भी सुदृढ़ किया है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक संपोषी वित्तपोषण के क्षेत्र में बाजार में अग्रणी रहा है। इंडिया एक्ज़िम बैंक के इस 2033 संपोषी बॉन्ड ने मार्च 2022 के पिछले निर्गम के 9 महीने बाद भारतीय निर्गमकर्ताओं के लिए जी3 बाज़ार को प्रभावी ढंग से फिर से खोल दिया। इसके अलावा, बैंक ने मार्च 2015 में यूएस डॉलर मूल्य वर्ग में भारत का पहला 5 वर्षीय रेग-एस हरित बॉन्ड जारी किया था। यह उस वर्ष एशिया में भी बेंचमार्क साइज का पहला हरित बॉन्ड था, जो अप्रैल 2020 में परिपक्व हुआ था। बैंक ने 2019 में यूएस डॉलर मूल्यवर्ग में पहला सामाजिक रूप से उत्तरदायी बॉन्ड जारी किया था।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने काला घोड़ा कला महोत्सव के लिए दिया सहयोग

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने इस साल 4 से 12 फरवरी तक होने वाले मुंबई के प्रतिष्ठित वार्षिक काला घोड़ा कला महोत्सव में सहयोग दिया है। इस महोत्सव में 60 से ज्यादा दस्तकारों ने अपनी अनूठी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया, जो इंडिया एक्ज़िम बैंक से एक दशक से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। बैंक ने इन्हें क्षमता विकास, प्रोडक्ट प्लेसमेंट और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए सहायता दी है।

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के दस्तकार इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था। इसमें हिस्सा लेने वाले कुछ दस्तकार और बुनकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हैं, जिनका कौशल, प्रतिभा और तकनीक उनके उत्पादों में परिलक्षित होते हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए मास्टर शिल्पकारों, बुनकरों, क्लस्टरों, स्वयं-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, ग्रासरूट और सूक्ष्म उद्यमों को क्षमता विकास, भारत और विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करने और उनके लिए विदेश में खरीदार तथा वितरक तलाशने में सहायता प्रदान करता है। बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई सहायता से वित्तीय सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, उद्यमिता बढ़ाने और देश के सदियों पुराने पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के पुनरुत्थान और भारतीय शिल्प विरासत को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।

इंडिया आईएनएक्स, गिफ्ट आईएफएससी में लिस्ट हुआ इंडिया एक्ज़िम बैंक का बेंचमार्क साइज़ का पहला 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड

इंडिया एक्ज़िम बैंक का 1 बिलियन यूएस डॉलर का पहला 10 वर्षीय संपोषी बॉन्ड 03 मार्च, 2023 को इंडिया आईएनएक्स, गिफ्ट आईएफएससी में लिस्ट हो गया। यह बॉन्ड बैंक के पर्यावरणीय सामाजिक गवर्नैंस (ईएसजी) फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया था। लिस्टिंग समारोह के दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री हर्षा बंगारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री तरुण शर्मा के साथ डॉ. विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास विशेष रूप से उपस्थित रहे।

भौगोलिक वितरण के लिहाज से देखा जाए तो इसका वितरण एमा (ईएमईए) क्षेत्र में 39%, एपेक में 32% और यूएसए में 29% रहा। यह वितरण उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों में रहा, जिनमें से लगभग 70% फंड और असेट मैनेजरों को, 12% बैंकों को और 10% संप्रभु वेल्थ फंड्स को रहा। इसके अलावा अन्य के साथ-साथ बीमा/पेंशन निगमों, निजी बैंकों ने भी बॉन्ड को सब्सक्राइब किया। संपोषी बॉन्ड से मिलने वाली इस राशि के इस्तेमाल की वार्षिक रिपोर्टिंग बाह्य सत्यापन पर निर्भर करेगी।

भारत के निर्यातों का पूर्वानुमान

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के लिए भारत के कुल मर्चैंडाइज़ निर्यातों के लिए पूर्वानुमान जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में, भारत के कुल मर्चैंडाइज़ निर्यातों के लगातार चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 100 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर रहते हुए, 110.9 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान है। इसी अवधि के दौरान, गैर-तेल निर्यात 87.7 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान है। भारत के निर्यात, वैश्विक ऊर्जा संकट, सख्त मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों, प्रमुख व्यापार भागीदारों में जारी मंदी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के चलते अनिश्चितताओं के अध्यधीन हैं। चालू वित्तीय वर्ष की पिछली दो तिमाहियों के दौरान निर्यातों में संकुचन के बावजूद, भारत के मर्चैंडाइज़ निर्यातों के वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 447.3 बिलियन यूएस डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। गैर-तेल निर्यात पूरे वर्ष के लिए 350.5 बिलियन यूएस डॉलर के बने रहने की उम्मीद है। ■

देशों का अवलोकन

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

मालदीव

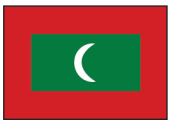

पर्यटन क्षेत्र में सुधार के साथ ही वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की उम्मीद है। 2022 में 11.5% की वृद्धि के बाद, अर्थव्यवस्था के 2023 में 7.7% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। मालदीव में वैश्विक कीमतें मुद्रास्फीति के रुझानों पर हावी हैं, क्योंकि घरेलू खपत मुख्य रूप से पर्यटन संबंधी व्यय से प्रेरित है और यह ज्यादातार आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। हालांकि 2023 में वैश्विक कीमतों में कमी आने की आशंका है, लेकिन कीमतों के ऐतिहासिक स्तर पर अधिक बने रहने की संभावना भी है। इससे विशेष रूप से भोजन, यूटिलिटी और परिवहन के लिए मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। 2023 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के अधिक होने का अनुमान है और कीमतों में औसतन 3.8% की वृद्धि हो सकती है। रूफिया (मालदीव की मुद्रा) का आकलन यूएस डॉलर के आधार पर होता है, विनिमय दर का मध्यबिंदु 1 यूएस डॉलर : आरएफ 12.85 है। इस दर में ± 20% के बैंड के भीतर उतार-चढ़ाव हो सकता है। उच्च (और बढ़ते) आयात बिल और मुद्रा को मिल रहे लगातार समर्थन के कारण मालदीव को 2023 में अपने बाहरी बफर्स के कम रहने की उम्मीद है। रूफिया विनिमय दर 2023 में 1 यूएस डॉलर 15.39 : के आसपास स्थिर रह सकती है। सेवा अधिशेष के बढ़ने से घाटा 2022 के जीडीपी के अनुमानित 21.6% से घटकर 2023 में जीडीपी के 15.8% तक पहुंच सकता है।

क्यूबा

क्यूबा के आर्थिक सुधार 2023 में धीरे-धीरे 3.8% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह कोविड-19 महामारी, सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों, 2021 में मुद्रा समायोजन के बाद मौद्रिक अस्थिरता और 2022 में मातनजस तेल डिपो की आग एवं तूफान इयान के कारण मरम्मत व पुनरुद्धार की अतिरिक्त लागत की वजह से पीछे रह गई थी। राजकोषीय समायोजन और आपूर्ति में क्रमिक सुधार (आर्थिक विकास में तेजी के बीच) अंततः 2021 की मुद्रा और मूल्य में उतार-चढ़ाव से होने वाले असर को कम कर सकते हैं। इससे 2027 के आखिर तक आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 5% से नीचे (और वास्तविक दर 20% से नीचे) आ सकती है। मुद्रा समायोजन के प्रयास अत्यधिक बाधक साबित हुए हैं। ऐसे में, अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि यह हालिया स्थिरीकरण स्थानीय मुद्रा "पेसो" के कमजोर होने के सिलसिले की समाप्ति का संकेत देता है या नहीं। फिर भी, ब्लैक मार्केट दर कम आंकी गई प्रतीत होती है, पेसो के सीयूपी 150 : 1 यूएस डॉलर तक मजबूत होने की उम्मीद है। मुद्रा समायोजन और दोहरी विनिमय-दर प्रणाली का संभावित एकीकरण निर्यात वृद्धि व आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करता है। लेकिन 2024-27 की दूसरे अर्धभाग तक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। वस्तुओं के निर्यात में मजबूती आने में अधिक समय लग सकता है, क्योंकि वित्तपोषण की कमी से उत्पादकों की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बाधित हो सकती है। आयात संबंधी व्यय संयुक्त रूप से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि को कम कर सकता है, जिससे बाद में चालू खाता अधिशेष बढ़ सकता है।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक व्यापक, निर्यात-उन्मुख विनिर्माण क्षेत्र की मेजबानी करता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और पेट्रोकेमिकल्स में उत्कृष्ट है। दक्षिण कोरिया की आर्थिक वृद्धि 2022 के 2.6% से घटकर 2023 में 1.3% होने की संभावना है क्योंकि बाहरी और घरेलू दोनों मांग कमजोर हो रही हैं। वैश्विक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में गिरावट का चक्र 2023 में लो-एंड सेमीकंडक्टर और पैनल स्क्रीन तक विस्तारित हो सकता है, जिसका असर निर्यात-उन्मुख विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। हालांकि, चीन के फिर से खुलने से मामूली बढ़त मिलने की संभावना है। 2023 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति औसतन 2.8% बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्ष 2022 में उच्च ब्याज दर के कारण 5.1% थी। औसतन, मुद्रा वॉन के 2022 के डब्ल्यू 1144 : 1 यूएस डॉलर से बढ़कर डब्ल्यू 1243 : 1 यूएस डॉलर होने की उम्मीद है। यह बढ़ते चालू खाता अधिशेष और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा समर्थित है। चालू खाते में 2022 के 1.9% की तुलना में 2023 में जीडीपी के 2.7% के बराबर अधिशेष दर्ज करने की उम्मीद है। वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी से आयात बिल कम हो सकता है।

सऊदी अरब

2022 में सऊदी अरब जी-20 सदस्य देशों के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अपनी दीर्घकालिक विविधीकरण योजना विजन-2030 के एक हिस्से के रूप में, देश गैर-पेट्रोलियम निर्यात में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। 2022 में 8.7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बाद, मुख्य रूप से तेल की ऊंची कीमतों की वजह से सऊदी अरब की आर्थिक वृद्धि 2023 में 2.8% तक कम होने की आशंका है। स्थिर औसत तेल उत्पादन और बढ़ती प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति बाधक हो सकती है। सऊदी अरब ओपेक+ द्वारा सहमत अपने उत्पादन कोटे का पालन करने के क्रम में स्थिर औसत तेल उत्पादन हासिल करता है। तथापि, अपनी जीरो कोविड नीति को अचानक छोड़ने के बाद चीन की विकास संभावनाओं में सुधार, सऊदी अरब के मुख्य निर्यात बाजार में मजबूत मांग सुनिश्चित करता है। 2023 में 2.2% की कम मुद्रास्फीति से व्यक्तिगत खपत को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है और आर्थिक विविधीकरण को लेकर सरकार का ध्यान ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर है। आर्थिक विकास सेवा-उन्मुख क्षेत्रों, विशेष रूप से पर्यटन और कई बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं से प्रेरित होने की संभावना है। यूएस डॉलर के मुकाबले सऊदी अरब की मुद्रा रियाल का मूल्य एसआर 3.75 : 1 यूएस डॉलर है और यह दर 1986 से चली आ रही है। इसकी बड़ी वित्तीय परिसंपत्तियों के कारण इसमें उतार-चढ़ाव नहीं दिखता है। अनुमानित कम तेल निर्यात राजस्व के कारण 2023 में चालू खाता अधिशेष जीडीपी के 6.5% तक सीमित हो गया। यह 2022 में उत्पन्न चालू खाता अधिशेष का आधा है। ■

मुद्राओं की स्थिति

सौजन्य : **ट्रेजरी और लेखा समूह**

ब्राजीलियन रियाल

ब्राजील की अर्थव्यवस्था में 2022 की चौथी तिमाही में 0.2% की गिरावट आई। यह उपभोक्ता कीमतों में तेजी और ब्याज दरों में भारी वृद्धि के असर से जूझ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील ने अपनी फरवरी की बैठक में नीतिगत दर (सेलिक ब्याज दर) को 13.75% पर बनाए रखा क्योंकि मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए इसका जोखिम दोनों क्षेत्रों में बना हुआ है। अमेरिका के लेखा घोटाले के दौरान, उच्च ब्याज दरें और ऋण की खराब स्थिति निवेश को कम कर सकती है और मंदी के जोखिम को बढ़ा सकती है। ऐसे में, सेंट्रल बैंक आगामी ब्याज दर संबंधी निर्णयों में बदलाव कर सकता है।

ब्राजीलियन रियाल (बीआरएल) पिछले कुछ दिनों में अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से लगभग 5.21/यूएस डॉलर से अधिक कमजोर हो गया है और अब उस स्तर की ओर वापस लौटने की संभावना है। हालांकि, आगामी अक्टूबर के राष्ट्रपति चुनाव में बाजार की अस्थिरता की चिंताओं को खारिज करते हुए, 2022 की दूसरी तिमाही में कमजोर अवधि के बाद महीनों से यह 5.20/यूएस डॉलर के करीब अपेक्षाकृत स्थिर रही है।

15 मार्च 2023 को यूएस डॉलर के मुकाबले बीआरएल 5.2882 पर बंद हुआ।

जापानी येन

बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने हालिया नीतिगत बैठक में अपनी अत्यधिक-आसान मौद्रिक नीति को अपरिवर्तित रखा। इसके अलावा, इसने अपनी यील्ड कर्व कंट्रोल नीति को बनाए रखा और बिना किसी सीमा के सरकारी बॉन्ड खरीदने की अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा।

येन की मौजूदा तेजी सितंबर के मुकाबले बड़ा परिवर्तन है जब फेडरल रिजर्व और डोविश बीओजे के बीच प्रतिफल का अंतर बढ़ने के कारण हेज फंड्स की कमी हो गई। उस विचलन ने 25% की गिरावट के साथ मुद्रा को पिछले वर्ष के निचले स्तर तक पहुंचाया। अक्टूबर 2022 में निर्धारित तीन दशक के निचले स्तर 151.95 प्रति यूएस डॉलर से अब येन में 16% की बढ़ोतरी हुई। यह सुधार मुद्रा को समर्थन देने के लिए सरकार के हस्तक्षेप और अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि को धीमा करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो बॉन्ड प्रतिफल को बढ़ा सकता है। देश की परिसंपत्तियों में फंड्स को आकर्षित कर सकता है।

यूएस डॉलर और जापानी येन (जेपीवाई) को हाल ही में वैश्विक बैंकिंग संकट की नई आशंकाओं से समर्थन मिला, जो अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के बाद अटलांटिक में स्विस बैंक क्रेडिट सुइस तक फैल गया। जापानी येन के एक सुरक्षित मुद्रा होने के कारण, बैंकिंग संकट से लगभग 4% का लाभ हुआ।

यह जोड़ी 15 मार्च 2023 को यूएस डॉलर/जेपीवाई 133.40 पर बंद हुई।

श्रीलंकाई रुपया

वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन, कमजोर शासन और खराब नीतिगत विकल्पों के कारण श्रीलंका वर्तमान में अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जैसे बाहरी कारकों ने देश की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप 1948 में अंग्रेजों से आजादी के बाद से यह अब तक का सबसे खराब संकट है।

दिवालिया राष्ट्र 2022 के अधिकांश समय में बढ़ती लागत, कम धन और गंभीर आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है क्योंकि इसने पिछले साल मई में ऋण चूक के बाद आईएमएफ से ऋण हासिल किया। संकट की स्थिति से उबरने के लिए, श्रीलंका फंड का नए सिरे से इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही ऊर्जा सब्सिडी में कटौती, करों में वृद्धि और ब्याज दरों को 2001 के बाद से सबसे अधिक 15.5% तक बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए हैं।

श्रीलंकाई रुपया फरवरी 2023 तक यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 360 की स्थिर विनिमय दर पर बना रहा। 07 मार्च 2023 से, सेंट्रल बैंक पूर्व-घोषित आकलन के बजाय तदर्थ आकलन पर काम कर रहा है, जो लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। यहां बैंक के हस्तक्षेप से अस्थिर गति स्थिर होगी। इसके अलावा, सरेंडर नियम में ढील से बैंकों के पास डॉलर की तरलता बढ़ी और श्रीलंकाई रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 305 हो गया।
15 मार्च 2023 को एक यूएस डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया 335 के मूल्य पर बंद हुआ।

ओमानी रियाल

ओमान की अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों पर आधारित है क्योंकि यह दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है। ओमान का तेल और गैस उद्योग देश की जीडीपी का लगभग एक तिहाई और निर्यात किए गए माल का लगभग 60% हिस्सा है। अन्य खाड़ी देशों की तरह, ओमान को भी तेल की ऊंची कीमतों के कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से फायदा हो रहा है।

ओमानी रियाल (ओएमआर) कुवैती दीनार और बहरीन दीनार के बाद दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान मुद्रा इकाई है। यह सल्तनत एक निश्चित विनिमय-दर व्यवस्था का पालन करती है और परिणामस्वरूप इसकी ब्याज दर यूएस दरों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान की रेपो दर आमतौर पर यूएस फेडरल रिजर्व नीति दर के अनुरूप होती है। यूएस फेडरल रिजर्व के नेतृत्त्व के बाद, ओमान ने 2022 और 2023 में लगातार आठ दर संशोधनों में अपनी प्रमुख नीतिगत दर को 5.25% तक बढ़ा दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है और निरंतर बना हुआ है। साथ ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करके इसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने पिछले नवंबर में राजकोषीय प्रदर्शन, तेल की ऊंची कीमतों और कम सार्वजनिक ऋण के कारण ओमान की क्रेडिट रेटिंग बीबी- से बीबी तक बढ़ा दी है।
15 मार्च 2023 को यूएस डॉलर की तुलना में ओएमआर 0.38488 पर बंद हुआ। ■

एक्ज़िम मित्र

सौजन्य: **एक्ज़िम मित्र समूह**

भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार वित्त, ऋण बीमा और व्यापार से जुड़ी अन्य जानकारियों के प्रसार की विषमता को दूर करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। निर्यात के लिए ऋण उपलब्धता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। एक्ज़िम मित्र के जरिए ऐसे प्रयास करना, जिनसे भारतीय उद्यमियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया हैं:

खाखरा (डाइट खाखरा) के निर्यात के लिए पंजीकरण और सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) और पैंकिंग मानकों के बारे में जानकारी

आयात या निर्यात के लिए कोई भी लाइसेंस/प्राधिकार प्राप्त करने और एफटीपी के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए आरसीएमसी अनिवार्य है। चूंकि खाखरा एक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, इसलिए एपीडा आरसीएमसी जारी करता है। कोई भी व्यक्ति एपीडा की वेबसाइट से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ- विविध व्यंजनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। खाखरा के निर्यात के लिए किसी खास तरह की पैकेजिंग की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त उपभोक्ता पैकेज (प्राथमिक पैकिंग) में वस्तुओं को पैक करना चाहिए और फिर उन पैकेजों को समुद्र के वातावरण अनुकूल पैकेजिंग (द्वितीयक पैकिंग) में रखना चाहिए, जो वस्तुओं को समुद्री यात्रा की कठिनता का सामना करने और रास्ते में खराब होने से बचाने में मदद करेगी। कोई भी व्यक्ति भारतीय पैकेजिंग संस्थान से संपर्क करके पैकेजिंग उद्योग में नवीनतम विकास के साथ-साथ आवश्यक तकनीकी विशिष्टताओं पर विस्तृत सलाह ले सकता है।

भारत से मर्चेंडाइज निर्यात योजना (एमईआईएस) पुरस्कार के बारे में जानकारी

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 3 के तहत, एमईआईएस और एसईआईएस जैसी योजनाएं हैं जो कुछ वस्तुओं या सेवाओं के निर्यातकों को लाभ प्रदान करती हैं। इसका उद्देश्य भारत से निर्यात करते समय निर्यातकों के सामने आने वाली ढांचागत अक्षमताओं और अन्य लागतों की भरपाई करने के लिए निर्यातक को पुरस्कृत करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है। एमईआईएस लाभों के लिए पात्रता वस्तुओं के प्रकार और निर्यात किए जाने वाले देश पर आधारित है जिसे डीजीएफटी वेबसाइट पर महत्त्वपूर्ण लिंक के जरिए या एफटीपी के परिशिष्ट 3बी के तहत देखा जा सकता है। एमईआईएस पुरस्कार एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) शर्तों में मापे गए निर्यात के कुल मूल्य का एक प्रतिशत है जो आमतौर पर 2 से 5% के बीच होता है। एफओबी द्वारा, माल की कीमत घरेलू बंदरगाह पर लोडिंग के समय मापी जाती है और इसमें लोडिंग, शिपमेंट व बीमा लागत शामिल नहीं होती है। यह पुरस्कार नकद राशि में नहीं बल्कि हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में दिया जाता है।

क्या एकाधिक वस्तुओं के निर्यातक को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और बोर्डों के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है या एफआईईओ के साथ पंजीकरण ही काफी है?

भारत में 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं जो निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण हैं और विदेश व्यापार नीति 2009-14 द्वारा निर्देशित हैं। इसके अलावा, भारत में पांच सांविधिक कमोडिटी बोर्ड (चाय, कॉफी, रबर, मसाले और तंबाकू) हैं। ईपीसी/बोर्ड से आरसीएमसी आवेदन के दौरान, एक निर्यातक को अपने मुख्य व्यवसाय की घोषणा करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई मसालों का निर्यातक है तो मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) को आरसीएमसी के रूप में माना जाएगा और ईपीसी के साथ किसी अन्य आरसीएमसी को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। एफआईईओ अपनी बहु-उत्पाद समूह श्रेणी के तहत आरसीएमसी जारी कर सकता है, यदि निर्यात उत्पाद जिसके लिए पंजीकरण की मांग की गई है, दो अलग-अलग निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कवर किए गए कम से कम दो उत्पाद समूहों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित परिषद के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। बहु-उत्पाद निर्यातकों के लिए, जो किसी भी ईपीसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं या जहां व्यवसाय का दायरा अभी तय नहीं हुआ है तो निर्यातक के पास एफआईईओ से आरसीएमसी प्राप्त करने का विकल्प है।

प्री-शिपमेंट क्रेडिट के बारे में विवरण

प्री-शिपमेंट क्रेडिट से आशय किसी निर्यातक को शिपमेंट से पहले माल की खरीद, प्रसंस्करण, विनिर्माण या पैकिंग के वित्तपोषण के लिए बैंक द्वारा दिए गए किसी भी ऋण, अग्रिम या अन्य क्रेडिट से है। यह किसी विदेशी खरीदार द्वारा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दिए गए साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) या भारत से वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए एक पुष्ट और अपरिवर्तनीय आदेश या किसी अन्य प्रमाण के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यशील पूंजी व्यय को भी संदर्भित करता है कि भारत से निर्यात आदेश निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है, जब तक कि बैंक से निर्यात आदेश या साख पत्र के मामले में छूट न मिल जाए।

पैकिंग क्रेडिट अग्रिम देने के लिए बैंक द्वारा लगने वाली अवधि आमतौर पर प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं पर निर्भर करेगी। जैसे- खरीद, निर्माण या प्रक्रिया (यदि आवश्यक हो) और संबंधित वस्तुओं को शिप करने/सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक समय। बैंक विभिन्न प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से वह अवधि तय करते हैं, जिसके लिए पैकिंग क्रेडिट अग्रिम दिया जा सकता है ताकि निर्यातक को माल भेजने/सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए यह अवधि पर्याप्त हो।

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

वस्तु व्यापार

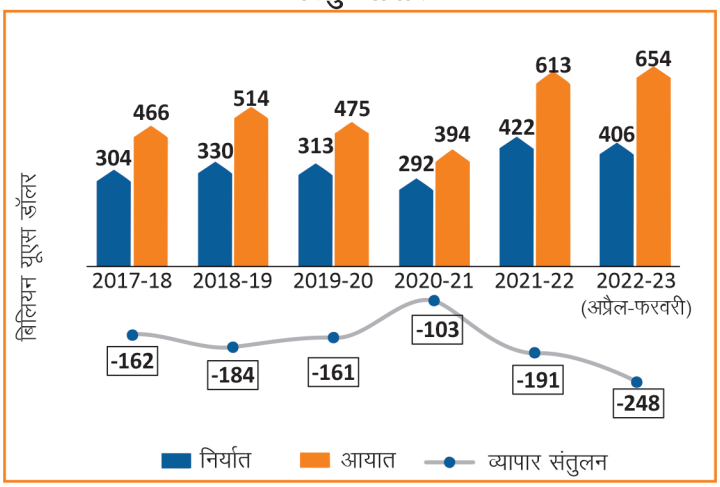

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवा व्यापार

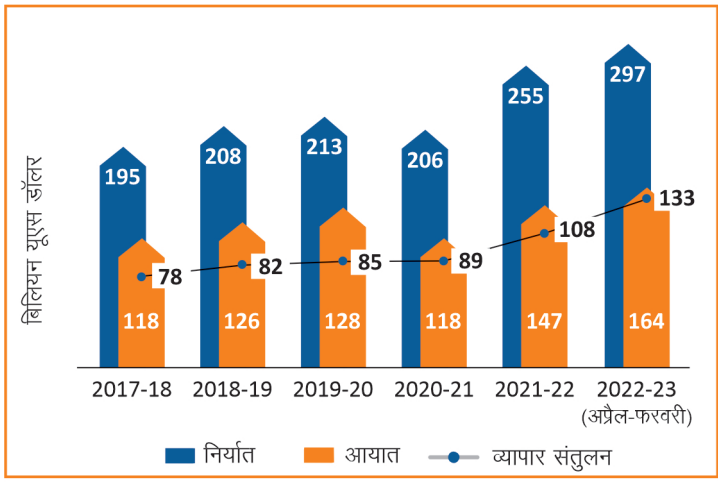

स्रोत: आरबीआई

चालू खाता घाटा

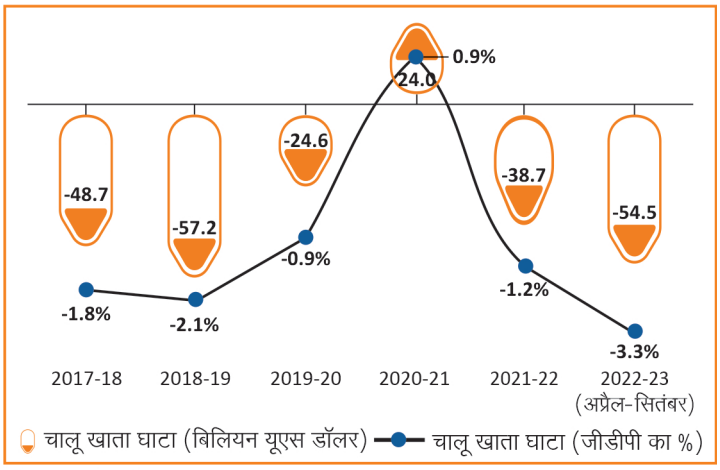

स्रोत: आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

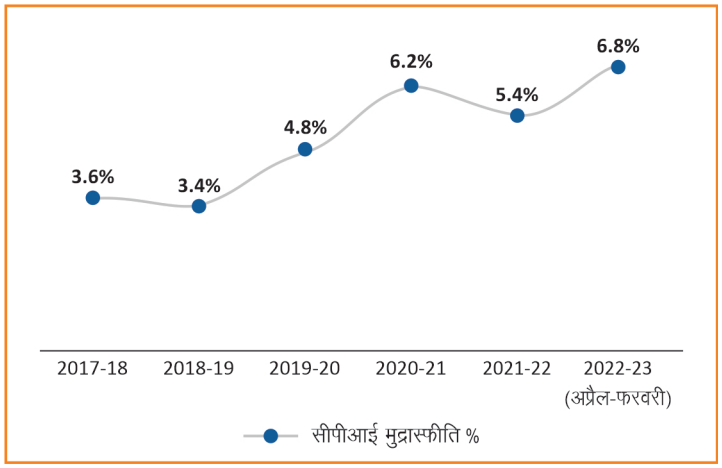

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निवेश का प्रवाह

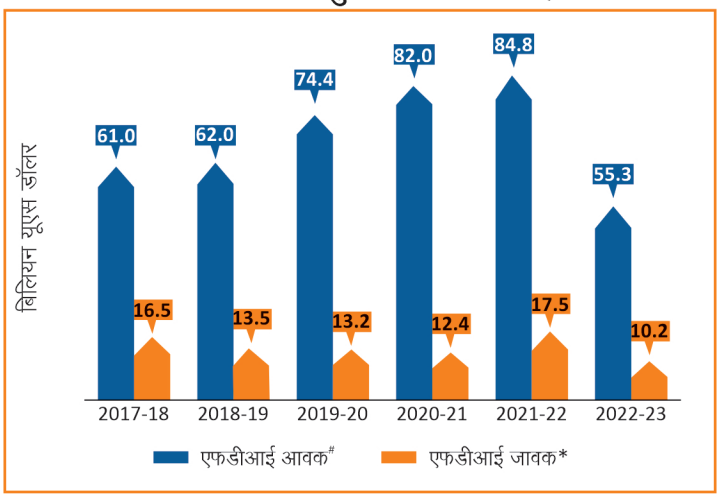

*नोट: *एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।*
#एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

क्षेत्रवार उत्पादन

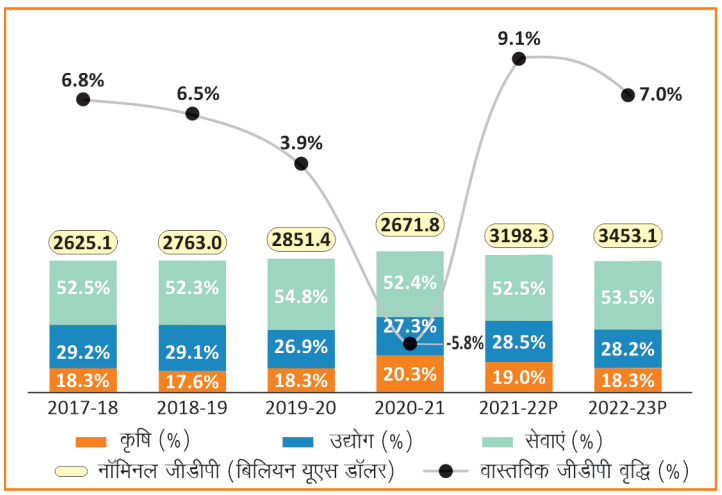

नोट: पीले रंग के आंकड़े नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर) को दर्शाते है ;
आरई– संशोधित अनुमान ; पीई– अंतिम अनुमान
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान फाइनेंस एंड सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार